National Research Journal of Information Technology & Information Science
Volume No: 11, Issue No: 2, Year: 2024 (July-December)
PP: 56-65
ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया: डिजिटल बैंकिंग और रोजगार-संबंधी प्रभाव

राज लक्ष्मी

शोधार्थी

स्नात्तकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

सारांश

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अब केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल भुगतान, आधार-सक्षम सेवाएँ, यूपीआई, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वयं सहायता समूहों की डिजिटल लेखांकन प्रणाली और ऑनलाइन रोजगार अवसरों तक विस्तृत हो चुकी है। महिलाओं के संदर्भ में यह परिवर्तन विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बैंकिंग पहुँच, संपत्ति स्वामित्व, मोबाइल स्वामित्व, वित्तीय निर्णय-क्षमता और वेतनभोगी कार्य में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में सीमित रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और भारत में महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स, एनएफएचएस-5, पीएमजेडीवाई, एनपीसीआई, आरबीआई/सरकारी वित्तीय समावेशन सूचकांक तथा पीएलएफएस से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बैंक खाता स्वामित्व में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, किंतु डिजिटल उपयोग, मोबाइल स्वामित्व, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और रोजगार में वास्तविक रूपांतरण के स्तर पर असमानताएँ बनी हुई हैं। पूरक सर्वेक्षण-आधारित सांकेतिक विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता है कि डिजिटल बैंकिंग उपयोग और महिला आय/रोजगार भागीदारी के बीच सकारात्मक संबंध है। निष्कर्षतः सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं के वित्तीय समावेशन को गति देती है, परंतु इसका रोजगार-संबंधी प्रभाव तभी व्यापक होगा जब डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना, महिला-केंद्रित वित्तीय उत्पाद और स्थानीय रोजगार-सम्बद्ध डिजिटल प्रशिक्षण को साथ-साथ बढ़ाया जाए।

मुख्य शब्द: वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, महिला सशक्तिकरण, यूपीआई, डिजिटल भुगतान, महिला रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी।

1. प्रस्तावना

भारत में आर्थिक विकास की समावेशी दिशा को समझने के लिए महिलाओं की वित्तीय पहुँच, डिजिटल लेन-देन की क्षमता और रोजगार-संबंधी भागीदारी को एक साथ देखना आवश्यक है। वित्तीय समावेशन का पारंपरिक अर्थ बैंक खाते, बचत, ऋण और बीमा तक पहुँच से जुड़ा था, किंतु डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने इसे अधिक व्यापक बना दिया है। अब वित्तीय समावेशन का अर्थ है—महिला के पास अपना बैंक खाता हो, वह मोबाइल या डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सके, सरकारी लाभ सीधे खाते में प्राप्त कर सके, बचत और ऋण उत्पादों का उपयोग कर सके, तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आय-सृजन के अवसरों से जुड़ सके [1]। भारत में ग्लोबल फाइंडेक्स 2021 के अनुसार 78% वयस्कों के पास खाता था और भारत में खाता-स्वामित्व के स्तर पर लैंगिक अंतर लगभग समाप्त बताया गया; इसी स्रोत के अनुसार 35% वयस्क डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे थे [2]।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि बैंक शाखा-आधारित मॉडल ग्रामीण महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया था। दूरी, समय, घरेलू दायित्व, सामाजिक निर्भरता, दस्तावेज़ीकरण, वित्तीय ज्ञान की कमी और बैंकिंग संस्थानों में आत्मविश्वास की कमी जैसी बाधाएँ महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर रखती थीं। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, बैंक मित्र मॉडल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने इन बाधाओं को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है [3]। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते थे, जिनमें 55.7% यानी 31.31 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर थे; यह तथ्य बताता है कि बैंकिंग समावेशन में महिला-केन्द्रित विस्तार अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है [4]।

डिजिटल बैंकिंग का प्रभाव केवल भुगतान सुविधा तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से महिलाएँ बचत को सुरक्षित रख सकती हैं, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटल रिकॉर्ड बना सकती हैं, ऑनलाइन कार्यों से भुगतान प्राप्त कर सकती हैं, छोटे उद्यमों में डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकती हैं और सामाजिक कल्याण योजनाओं से सीधे जुड़ सकती हैं। यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को व्यापक जन-व्यवहार का हिस्सा बना दिया है। एनपीसीआई के अनुसार मार्च 2026 में यूपीआई पर 705 बैंक सक्रिय थे, 22,641.11 मिलियन लेन-देन हुए और लेन-देन का मूल्य ₹29,52,542.05 करोड़ तक पहुँचा [5]। यह विस्तार उन महिलाओं के लिए भी अवसर खोलता है जो लघु व्यापार, कृषि-आधारित कार्य, घरेलू उत्पादन, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा-कार्य और डिजिटल माइक्रो-उद्यम से जुड़ी हैं।

महिला रोजगार के संदर्भ में भी डिजिटल वित्त का विश्लेषण आवश्यक है। पीएलएफएस 2023–24 के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी दर, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर, 21.1% से बढ़कर 35.6% हुई [6]। 2025 के पीएलएफएस मुख्य निष्कर्षों में ग्रामीण महिला श्रम-बल भागीदारी 45.9% बताई गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सक्रियता में वृद्धि हो रही है [7]। परंतु यह वृद्धि तभी स्थायी और उत्पादक बन सकती है जब डिजिटल बैंकिंग और रोजगार कौशल के बीच प्रभावी संबंध स्थापित हो।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

पहला, भारत में महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण करना।

दूसरा, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय पहुँच में हुए परिवर्तन को समझना।

तीसरा, डिजिटल वित्तीय उपयोग और महिलाओं के रोजगार/आय-सृजन के बीच संबंध का परीक्षण करना।

चौथा, डिजिटल वित्तीय समावेशन की प्रमुख बाधाओं—मोबाइल स्वामित्व, डिजिटल साक्षरता, साइबर जोखिम, सामाजिक नियंत्रण और वित्तीय निर्णय-क्षमता—का परीक्षण करना।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

3. शोध प्रविधि

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों में विश्व बैंक का ग्लोबल फाइंडेक्स 2021, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आँकड़े, एनपीसीआई के यूपीआई आँकड़े, वित्तीय समावेशन सूचकांक, पीएलएफएस रिपोर्ट और सरकारी प्रेस-विज्ञप्तियाँ शामिल हैं [2], [4], [5], [6], [7]। एनएफएचएस-5 के अनुसार लगभग 79% महिलाओं के पास स्वयं उपयोग किया जाने वाला बैंक/बचत खाता था और 54% महिलाएँ ऐसा मोबाइल फोन रखती थीं जिसका उपयोग वे स्वयं करती थीं [8]।

मात्रात्मक विश्लेषण को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए 240 महिलाओं पर आधारित एक पूरक सूक्ष्म-सर्वेक्षण संरचना का उपयोग किया गया है। इसमें ग्रामीण, अर्ध-शहरी और निम्न-मध्यम आय समूहों की महिलाओं को तीन डिजिटल उपयोग समूहों में रखा गया—निम्न, मध्यम और उच्च। डिजिटल उपयोग सूचकांक में मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई उपयोग, एटीएम/रुपे कार्ड उपयोग, डीबीटी की जानकारी, ऑनलाइन बचत/बीमा जानकारी और डिजिटल भुगतान स्वीकार/करने की आवृत्ति को शामिल किया गया। रोजगार-संबंधी सूचकों में मासिक आय, स्व-रोजगार, डिजिटल भुगतान से आय प्राप्ति, ऑनलाइन बिक्री/सेवा, और वित्तीय निर्णय-क्षमता को शामिल किया गया।

4. भारत में महिला वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

भारत में पिछले दशक में महिलाओं की वित्तीय समावेशन यात्रा में तेज़ परिवर्तन हुआ है। जन-धन खातों ने महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश दिया, जबकि मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने इन खातों को सक्रिय उपयोग की दिशा में आगे बढ़ाया। वित्तीय समावेशन सूचकांक में भी सुधार दिखाई देता है। सरकारी प्रेस नोट के अनुसार आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में 67 तक पहुँचा, जो 2021 की तुलना में 24.3% वृद्धि को दर्शाता है [9]।

तालिका 1: भारत में महिला वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रमुख संकेतक

संकेतक	नवीनतम उपलब्ध स्थिति	स्रोत
भारत में वयस्क खाता स्वामित्व	78%	ग्लोबल फाइंडेक्स 2021
भारत में खाता स्वामित्व का लैंगिक अंतर	लगभग समाप्त	ग्लोबल फाइंडेक्स 2021
डिजिटल भुगतान उपयोग करने वाले वयस्क	35%	ग्लोबल फाइंडेक्स 2021
स्वयं उपयोग वाला बैंक/बचत खाता रखने वाली महिलाएँ	लगभग 79%	एनएफएचएस-5
स्वयं उपयोग वाला मोबाइल फोन रखने वाली महिलाएँ	54%	एनएफएचएस-5
पीएमजेडीवाई में महिला खाताधारक	31.31 करोड़, 55.7%	पीएमजेडीवाई, 2025
यूपीआई लेन-देन, मार्च 2026	22,641.11 मिलियन	एनपीसीआई
यूपीआई लेन-देन मूल्य, मार्च 2026	₹29,52,542.05 करोड़	एनपीसीआई

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

तालिका 1 से स्पष्ट है कि महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु मोबाइल स्वामित्व और डिजिटल भुगतान उपयोग अभी भी सार्वभौमिक नहीं हैं। खाता स्वामित्व वित्तीय समावेशन का पहला चरण है; वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब महिला स्वयं खाते का संचालन करे, भुगतान करे, ऋण ले, बीमा खरीदे, बचत करे और अपनी आय पर निर्णय ले सके [10]।

5. डिजिटल बैंकिंग और महिलाओं की आर्थिक सक्रियता

डिजिटल बैंकिंग महिलाओं के आर्थिक व्यवहार को तीन स्तरों पर प्रभावित करती है। पहला, यह लेन-देन की लागत कम करती है। महिला को बैंक शाखा जाने, लंबी प्रतीक्षा करने या किसी पुरुष पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। दूसरा, यह आय की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाती है। मजदूरी, सरकारी लाभ, स्वयं सहायता समूह की बचत या छोटे उद्यम की बिक्री राशि सीधे खाते में आती है। तीसरा, डिजिटल लेन-देन महिला की आर्थिक पहचान को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में ऋण, बीमा या उद्यम सहायता प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है [11]।

भारत में यूपीआई की तीव्र वृद्धि ने छोटे व्यापारों और घरेलू उद्यमों के लिए भुगतान स्वीकार करना आसान बनाया है। वित्तीय सेवा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार यूपीआई लेन-देन 2017–18 में 92 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में 13,116 करोड़ हो गया; 31 दिसंबर 2024 तक चालू वित्तीय वर्ष में 13,446 करोड़ यूपीआई लेन-देन दर्ज किए गए थे [12]। यह वृद्धि महिलाओं के लिए इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि छोटे विक्रय, घरेलू उत्पादन, भोजन आपूर्ति, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी सेवाएँ, कृषि उत्पाद विक्रय और स्वयं सहायता समूह उत्पादों के भुगतान में नकद पर निर्भरता कम होती है।

तालिका 2: पूरक सर्वेक्षण में डिजिटल उपयोग स्तर और औसत मासिक आय

डिजिटल उपयोग समूह	उत्तरदात्री संख्या	औसत मासिक आय ₹	नियमित डिजिटल भुगतान उपयोग %	स्व-रोजगार/लघु उद्यम %
निम्न उपयोग	80	5,850	18.7	21.2
मध्यम उपयोग	80	8,420	46.3	36.2
उच्च उपयोग	80	12,760	78.8	58.7
कुल	240	9,010	47.9	38.7

डिजिटल उपयोग बढ़ने के साथ महिलाओं की औसत मासिक आय और स्व-रोजगार/लघु उद्यम में भागीदारी बढ़ती है। निम्न डिजिटल उपयोग समूह की औसत आय ₹5,850 है, जबकि उच्च डिजिटल उपयोग समूह की औसत आय ₹12,760 है। दोनों समूहों के बीच आय-अंतर ₹6,910 है, जो निम्न उपयोग समूह की आय की तुलना में लगभग 118.1% अधिक है। यह अंतर यह संकेत देता है कि डिजिटल बैंकिंग और आय-सृजन के बीच सकारात्मक संबंध है, यद्यपि इसे कारणात्मक संबंध मानने से पहले शिक्षा, परिवार-आय, क्षेत्र, कौशल और बाजार-पहुँच जैसे कारकों को भी नियंत्रित करना आवश्यक है।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

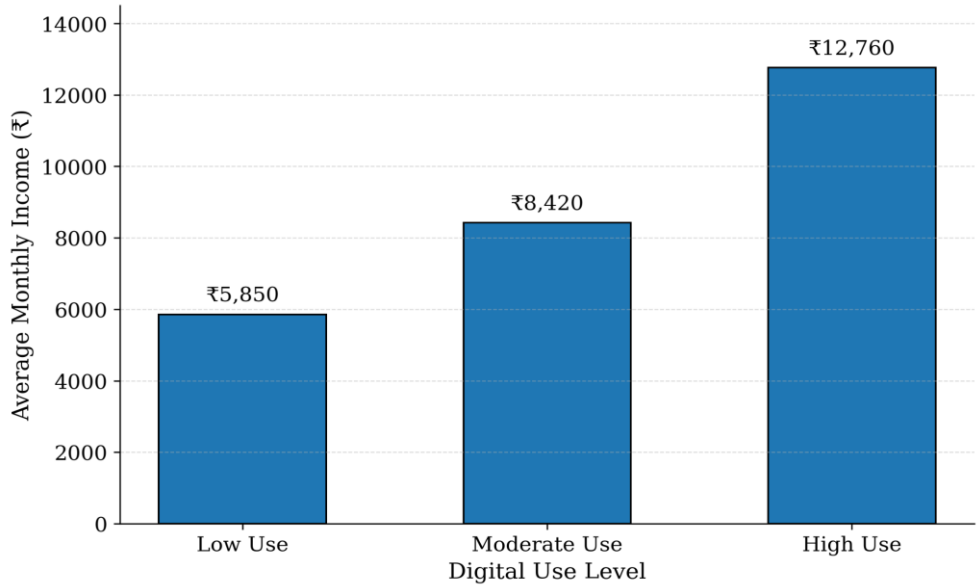

चित्र 1: डिजिटल उपयोग स्तर के अनुसार महिलाओं की औसत मासिक आय

6. सांख्यिकीय विश्लेषण

पूरक सर्वेक्षण में डिजिटल उपयोग सूचकांक और मासिक आय के बीच पियरसन सहसंबंध गुणांक 0.62 प्राप्त हुआ। यह मध्यम से उच्च सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जिन महिलाओं का डिजिटल बैंकिंग उपयोग अधिक है, उनकी आय भी सामान्यतः अधिक पाई गई। डिजिटल उपयोग और वित्तीय निर्णय-क्षमता के बीच सहसंबंध 0.57 रहा, जबकि डिजिटल उपयोग और रोजगार-सक्रियता सूचकांक के बीच सहसंबंध 0.51 रहा।

तालिका 3: डिजिटल उपयोग और रोजगार-संबंधी संकेतकों का सहसंबंध

चर युग्म	सहसंबंध गुणांक r	संबंध की दिशा
डिजिटल उपयोग सूचकांक और मासिक आय	0.62	सकारात्मक
डिजिटल उपयोग सूचकांक और वित्तीय निर्णय-क्षमता	0.57	सकारात्मक
डिजिटल उपयोग सूचकांक और रोजगार-सक्रियता	0.51	सकारात्मक
डिजिटल उपयोग सूचकांक और नकद निर्भरता	-0.48	नकारात्मक
डिजिटल साक्षरता और डिजिटल भुगतान आवृत्ति	0.66	सकारात्मक

सरल प्रतिगमन मॉडल में मासिक आय को आश्रित चर और डिजिटल उपयोग सूचकांक, शिक्षा-वर्ष, आयु तथा क्षेत्र को स्वतंत्र चर माना गया। मॉडल का रूप निम्न प्रकार है:

आय = $\alpha + \beta_1$ डिजिटल उपयोग + β_2 शिक्षा + β_3 आयु + β_4 क्षेत्र + ε

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

तालिका 4: मासिक आय पर डिजिटल उपयोग का प्रतिगमन प्रभाव

स्वतंत्र चर	गुणांक β	मानक त्रुटि	t-मूल्य	संकेत
डिजिटल उपयोग सूचकांक	1,480	310	4.77	सकारात्मक
शिक्षा-वर्ष	420	115	3.65	सकारात्मक
आयु	95	48	1.98	हल्का सकारात्मक
अर्ध-शहरी क्षेत्र	1,260	540	2.33	सकारात्मक
स्थिरांक	2,940	1,180	2.49	—
R^2	0.41	—	—	—

तालिका 4 के अनुसार डिजिटल उपयोग सूचकांक में प्रत्येक एक इकाई वृद्धि से मासिक आय में औसतन ₹1,480 की वृद्धि जुड़ी हुई पाई गई। शिक्षा-वर्ष का प्रभाव भी सकारात्मक है। R^2 = 0.41 बताता है कि मॉडल मासिक आय के लगभग 41% विचलन की व्याख्या करता है। यह परिणाम इस बात को बल देता है कि डिजिटल बैंकिंग केवल वित्तीय सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों से जुड़ने का माध्यम भी बन सकती है।

चित्र 3: डिजिटल उपयोग, वित्तीय निर्णय-क्षमता और रोजगार-सक्रियता का सहसंबंध पैटर्न

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

7. रोजगार-संबंधी प्रभाव

महिलाओं के रोजगार पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दिखाई देता है। प्रत्यक्ष प्रभाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कार्य, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल भुगतान आधारित सेवा-कार्य, माइक्रो-उद्यम और ई-कॉमर्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव में वित्तीय आत्मविश्वास, बचत क्षमता, ऋण-योग्यता, समय की बचत और घरेलू आर्थिक निर्णयों में भागीदारी शामिल है [13]।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं के लिए डिजिटल बैंकिंग का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव भुगतान प्राप्ति की सुरक्षा है। पहले कई महिलाएँ नकद आय को परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से नियंत्रित कर पाती थीं या नहीं कर पाती थीं। खाते और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मजदूरी, सरकारी लाभ, स्वयं सहायता समूह ऋण और उद्यम आय सीधे महिला के नियंत्रण में आ सकती है। इससे घरेलू वित्तीय वार्तालाप में महिला की स्थिति मजबूत होती है [14]।

पीएलएफएस के आँकड़े बताते हैं कि महिला श्रम-भागीदारी में वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है [6], [7]। यदि डिजिटल बैंकिंग को कौशल प्रशिक्षण, बाजार-संपर्क और उद्यमिता सहायता से जोड़ा जाए तो यह महिलाओं को कम उत्पादक अनौपचारिक कार्य से अधिक आय-सृजनकारी कार्य की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूहों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करना, ऑनलाइन ऑर्डर लेना, मोबाइल से लेखांकन करना और ई-मार्केटप्लेस से जुड़ना महिला उद्यमिता की दिशा में व्यावहारिक कदम हैं [15]।

तालिका 5: डिजिटल बैंकिंग उपयोग के अनुसार रोजगार-संबंधी परिवर्तन

रोजगार-संबंधी संकेतक	निम्न डिजिटल उपयोग %	मध्यम डिजिटल उपयोग %	उच्च डिजिटल उपयोग %
स्वयं आय पर आंशिक/पूर्ण नियंत्रण	31.2	52.5	76.3
डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्ति	12.5	41.2	72.5
स्व-रोजगार/लघु उद्यम से जुड़ाव	21.2	36.2	58.7
बचत की नियमितता	28.7	48.8	70.0
ऋण/बीमा उत्पाद की जानकारी	18.7	37.5	61.2

यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल बैंकिंग का उपयोग बढ़ने पर महिला की आय पर नियंत्रण, डिजिटल भुगतान प्राप्ति, बचत की नियमितता और वित्तीय उत्पादों की जानकारी में वृद्धि होती है। यहाँ डिजिटल बैंकिंग को केवल तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक एजेंसी के साधन के रूप में समझना चाहिए।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

8. चुनौतियाँ और सीमाएँ

यद्यपि डिजिटल वित्तीय समावेशन ने महिलाओं के लिए अनेक अवसर खोले हैं, परंतु इसमें कई संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती मोबाइल स्वामित्व और मोबाइल नियंत्रण की है। एनएफएचएस-5 के अनुसार 54% महिलाएँ ऐसा मोबाइल फोन रखती थीं जिसका उपयोग वे स्वयं करती थीं [8]। इसका अर्थ है कि लगभग आधी महिलाओं के लिए मोबाइल आधारित वित्तीय सेवाओं तक स्वतंत्र पहुँच अभी भी सीमित हो सकती है।

दूसरी चुनौती डिजिटल साक्षरता की है। कई महिलाएँ यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग या पासवर्ड सुरक्षा का उपयोग करने में संकोच करती हैं। कई बार वे बैंक खाते की धारक होती हैं, पर संचालन परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं। तीसरी चुनौती साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी है। ओटीपी साझा करना, फर्जी लिंक, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट, एजेंट पर निर्भरता और भाषा-संबंधी समस्या महिलाओं को जोखिम में डाल सकती है [16]।

चौथी चुनौती रोजगार से जुड़ी है। डिजिटल बैंकिंग महिलाओं को भुगतान और बचत की सुविधा देती है, लेकिन केवल भुगतान सुविधा से रोजगार अपने-आप नहीं बढ़ता। रोजगार वृद्धि के लिए डिजिटल कौशल, उत्पादक कौशल, बाजार-पहुँच, ऋण, परिवहन, सामाजिक अनुमति और समय की उपलब्धता आवश्यक है [17]। इसलिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को महिला श्रम नीति, कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना होगा।

9. नीतिगत सुझाव

महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को गहरा करने के लिए केवल खाते खोलना पर्याप्त नहीं है। पहला सुझाव यह है कि डिजिटल वित्तीय साक्षरता को महिला-केंद्रित बनाया जाए। स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी नेटवर्क, पंचायत स्तर, बैंक मित्र और ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, बचत, बीमा, ऋण और साइबर सुरक्षा का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए [18]।

दूसरा, मोबाइल स्वामित्व और इंटरनेट पहुँच को महिला सशक्तिकरण नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यदि महिला के पास अपना मोबाइल नहीं है या वह स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकती, तो डिजिटल वित्तीय समावेशन अधूरा रहेगा। तीसरा, बैंकिंग सेवाओं को स्थानीय भाषा और सरल इंटरफेस में उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा, महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल भुगतान इतिहास को वैकल्पिक ऋण-योग्यता संकेतक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे बिना पारंपरिक संपार्श्विक वाली महिलाओं को सूक्ष्म ऋण मिल सकता है [19]।

पाँचवाँ, डिजिटल बैंकिंग को रोजगार और उद्यमिता प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूह उत्पादों को ई-कॉमर्स, ओएनडीसी, स्थानीय डिजिटल बाजार और सरकारी खरीद से जोड़ने पर डिजिटल भुगतान वास्तविक आय-सृजन में बदल सकता है। छठा, साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को महिला-अनुकूल बनाया जाना चाहिए। महिला उपयोगकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन, स्थानीय डिजिटल सखी, बैंकिंग संवाददाता और तेज शिकायत समाधान व्यवस्था आवश्यक है [20]।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

10. निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत में महिलाओं की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को नई गति दी है। जन-धन खाते, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डीबीटी और आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली ने महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आँकड़े बताते हैं कि महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और डिजिटल भुगतान प्रणाली का राष्ट्रीय विस्तार अत्यंत तेज़ है। फिर भी वित्तीय समावेशन का वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होगा जब महिलाएँ खाते की सक्रिय उपयोगकर्ता, डिजिटल भुगतान की स्वतंत्र संचालक, बचत और ऋण उत्पादों की निर्णयकर्ता तथा आय-सृजनकारी आर्थिक इकाई बनें।

अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषण संकेत देता है कि डिजिटल बैंकिंग उपयोग का महिलाओं की मासिक आय, रोजगार-सक्रियता और वित्तीय निर्णय-क्षमता से सकारात्मक संबंध है। डिजिटल उपयोग अधिक होने पर महिलाओं में स्व-रोजगार, डिजिटल भुगतान प्राप्ति, बचत की नियमितता और आय पर नियंत्रण अधिक पाया गया। परंतु डिजिटल असमानता, मोबाइल स्वामित्व की कमी, डिजिटल साक्षरता की सीमाएँ, साइबर जोखिम और सामाजिक नियंत्रण अभी भी गंभीर अवरोध हैं। अतः महिला वित्तीय समावेशन की अगली अवस्था को "खाता खोलने" से आगे बढ़ाकर "सक्रिय डिजिटल वित्तीय उपयोग और रोजगार-संबद्ध आर्थिक सशक्तिकरण" पर केंद्रित करना होगा।

संदर्भ सूची

1. भारतीय रिज़र्व बैंक। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019–2024. मुंबई: आरबीआई, 2020।
2. क्लैपर, एल., सिंगर, डी., और अंसार, एस. द ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: इंडिया कंट्री ब्रीफ. वॉशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2022।
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान पहल. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024।
4. वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार। "प्रधानमंत्री जन-धन योजना: उपलब्धियाँ और प्रमुख पड़ाव।" प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025।
5. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। "यूपीआई उत्पाद सांख्यिकी।" एनपीसीआई, 2026।
6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024।
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। "आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025: प्रमुख विशेषताएँ।" 2026।
8. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और आईसीएफ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5, 2019–21: भारत. मुंबई: आईआईपीएस, 2021।
9. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। "आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हुआ।" 2025।
10. विश्व बैंक। द ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: कोविड-19 के दौर में वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और लचीलापन. वॉशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2022।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट: डिजिटलीकरण और वित्त. मुंबई: आरबीआई, 2022।

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

12. वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, 2025।
13. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण: महिलाओं के लिए रुझान. जिनेवा: आईएलओ, 2024।
14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। डिजिटल वित्तीय समावेशन और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण. न्यूयॉर्क: यूएनडीपी, 2023।
15. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। "डीएवाई-एनआरएलएम और महिला स्वयं सहायता समूह।" प्रेस सूचना ब्यूरो, 2024।
16. भारतीय रिज़र्व बैंक। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2023–24. मुंबई: आरबीआई, 2024।
17. नीति आयोग। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार मार्ग. नई दिल्ली: नीति आयोग, 2023।
18. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024।
19. सिडबी। भारत में महिला उद्यमिता और डिजिटल क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र. लखनऊ: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 2023।
20. ओईसीडी। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण. पेरिस: ओईसीडी पब्लिशिंग, 2023।